

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Fin-IF-A(3)-1/2020 dated as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Finance -IF Department

No. Fin-IF-A(3)-1/2020 dated Shimla-2

28th November, 2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 20 B of the Specific Relief Act 1963, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh is pleased to designate all the Courts of Civil Judges and Senior Civil Judges in the State of Himachal Pradesh as well as the court of Additional District and Sessions Judge-I in each District as Special Courts within the local limits of the area to exercise jurisdiction and to try a suit under the Act ibid in respect of contracts relating to infrastructure projects.

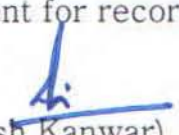
By Order,

Prabodh Saxena, IAS
Addl. Chief Secretary (Finance) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst No. As above, dated, Shimla- 171002 28-11-2020.

Copy to :

1. All the District Session Judges in the State of H.P.
2. All the Administrative Secretaries to the Government of H.P.
3. All the Head of Departments in the State of H.P.
4. The Registrar General, H.P. High Court, Shimla.
5. All the District Magistrates in the State of H.P.
6. All the Sub-Divisional Magistrates in the State of H.P.
7. All the Superintends of Police in the State of H.P.
8. The Controller, Printing and Stationery, Shimla-5, H.P. He is requested to publish the above notification in the Rajpatra (Extra-ordinary) and send five copies of the same to this department for record.


(Rakesh Kanwar), IAS
Special Secretary (IF) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त विभाग

संख्या:फिन-आईएफ-ए(3)-1/2020, दिनांक, शिमला-2, 28 नवम्बर,2020

अधिसूचना


हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम,1963 की धारा 20 आ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से हिमाचल प्रदेश राज्य में सिविल न्यायाधीशों और सीनियर सिविल न्यायाधीशों के समस्त न्यायालयों के साथ-साथ प्रत्येक जिला में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I के न्यायालयों को, अवसरचरणात्मक परियोजनाओं से सम्बन्धित संविदाओं की बाबत, पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर अधिकारिता का प्रयोग करने और किसी वाद का विचारण करने हेतु विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करते हैं।

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना, आई0ए0एस.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या उपरोक्त। दिनांक शिमला-2 28 नवम्बर, 2020

1. सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश।
2. सभी प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. सभी विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
4. रजिस्ट्रार जनरल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला, हि0 प्र0।
5. सभी जिला मैजिस्ट्रेट, हिमाचल प्रदेश।
6. सभी उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, हिमाचल प्रदेश।
7. सभी पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश।
8. नियंत्रक,प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, हि0 प्र0, शिमला से आग्रह है कि उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र (असाधारण) के प्रकाशित करें और पांच प्रतियां इस विभाग को रिकार्ड हेतु भेजें।


(राकेश कवर), आई0ए0एस0
विशेष सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार।